लाल बहादुर और अन्य

बनाम

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

(आपराधिक अपील संख्या 1794/2008)

8 अप्रैल, 2013

[पी. सतशिवम और एम. वाई. एक्बाल, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860- धाराएँ 147 / 149 / 449 / 436 / 302 / 395 /396 भारत के प्रधानमंत्री की हत्या-सांप्रदायिक दंगे सिख समुदाय पर हिंसक हमला-भीड़ की हत्या पीडब्लू 1 के पति और ससुर और सामान लूटना अभियुक्त-अपीलार्थियों को बरी करना-द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटना उच्च न्यायालय-औचित्य-आयोजितःन्यायोचित-गवाह द्वारा किए गए अपराध के संबंध में लगातार अपदस्थ अपीलार्थी और उनके साक्ष्य अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अडिग रहे-केवल मामूली भिन्नता और गवाह की विश्वसनीयता-पीड़ित के शव की खोज हत्या में कार्पस डिलिक्टि साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है-वास्तव में, इस तरह के प्रकृति के बहुत सारे मामले हैं जैसे वर्तमान में जहाँ मृत शरीर की खोज की गई थी असंभव, विशेष रूप से जब किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की इस तरह के हिंसक भीड़ हमले में हत्या कर दी गई थी विभिन्न स्थानों पर सिख

समुदाय और अपराधियों ने कोशिश की शवों को हटा दें और सामान भी लूट लें-उच्च न्यायालय ने सबूतों की सही सराहना की और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया

आपराधिक मुकदमा - सबूत - प्रशंसा - भारत के प्रधानमंत्री की हत्या-सांप्रदायिक दंगे भीड़ ने पीडब्लू 1 के पति और ससुर की हत्या की-मामले में पुलिस द्वारा देरी एफ. आई. आर. दर्ज करना और गवाहों के बयान दर्ज करना- आयोजितः अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं किया -अचानक हुई घटना अकेली नहीं थी, ऐसी घटनाएं देश के लगभग सभी हिस्सों में हुईं-मामले की परिस्थितियाँ इसे महत्व देना या पूरी तरह से अनदेखा करना-इसके अलावा, इससे पहले गवाह घटना उसी क्षेत्र के निवासी थे और उन्हें पता था कि हमलावरों और यह अपीलार्थियों का मामला नहीं था कि देरी के परिणामस्वरूप गलत पहचान हो सकती थी अभियुक्त-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 147 / 149 / 449 / 436 / 302 / 395 /396 .

अपील-दोषमुक्त करने की शक्ति के विरुद्ध अपील- अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पुनः सराहना करने के लिए आयोजितः अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है-उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने का अधिकार

है कि क्या निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं। अनुचित है।

31 अक्टूबर, 1984 को दिवंगत प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए। एक भीड़ अपीलार्थी सं.1 सहित अपीलार्थी सं. 2 कथित तौर पर पीडब्लू 1 के घर पर हमला किया और घरेलू सामान लूटपाट की। पीडब्लू 1 अपने पति के साथ और ससुर ने पीडब्लू-5 के आवास पर शरण ली। 3 नवंबर, 1984 को 500 से अधिक लोगों की भीड़, अपीलार्थियों सहित और उनके नेतृत्व में, आए और हमला किया पीडब्लू का घर-5। अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर तोड़ दिया, घर की खिड़की खोलकर अंदर घुसा और घर में आग लगा दी। पीडब्लू 1 के पति और ससुर को जिंदा जला दिया गया और उनके आधे जले हुए शरीर को बोरे में डाल दिया गया। पीडब्लू 1 का घर भी जला दिया गया था।

निचली अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष विफल रहा अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सभी उचित संदेह से परे साबित करें और उन्हें बरी कर दें। राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी गई जिसने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और आरोपी अपीलार्थियों को आई.पी.सी. की धारा 147/149/449 436/302/395/396 और इसलिए वर्तमान अपील के तहत दोषी ठहराया।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए यह **अभिनिर्धारित किया गया**

1. तत्काल घटना, जैसा कि आरोप लगाया गया है, ऐसी नहीं है एकल घटना, लेकिन ऐसी घटनाएं देश के लगभग सभी हिस्सों में हुईं, विशेष रूप से दिल्ली में जहां कई एक समुदाय के निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। और उनकी संपत्तियों को लूटा गया था क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या, जो यह 31 अक्टूबर, 1984 को हुआ था। प्रधानमंत्री की हत्या की चौंकाने वाली खबर सुनने के बाद, हजारों लोग विभिन्न क्षेत्रों में भीड़ बना रहे हैं और स्थानीय लोगों ने सिख समुदायों पर अत्याचार किए और उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें आग लगा दी गई। इसलिए, सबूतों की सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए साक्ष्य में मामूली विसंगतियों और विरोधाभासों में। [पैरा 11] [758-डी-एफ]

2. देरी के मुद्दे पर उच्च न्यायालय एफ. आई. आर. दर्ज करने में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान की परिस्थितियाँ मामला असाधारण है क्योंकि देश इसमें डूबा हुआ था lkEiznkf;d दंगे, कर्फ्यू लगा दिया गया, सिख परिवारों को अनियंत्रित और कट्टर पुरुषों की भीड़ द्वारा निशाना बनाया जा रहा था जो मानव जीवन को समाप्त करने से डरते नहीं थे, संपत्ति को नष्ट करने/जलाने की तो बात ही छोड़िए। बयानों की रिकॉर्डिंग के संबंध में 27 दिनों की देरी के बाद 30 नवंबर, 1984 को पुलिस द्वारा गवाहों के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि शहर में

उथल-पुथल थी और ऐसे लोग जिन्होंने अपराध देखे थे स्वाभाविक रूप से आने में आशंकित और भयभीत होंगे, अपराधियों के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे बढ़ें, जब तक कि चीजें न हों; राज्य तंत्र पर अधिक काम किया गया था; और ऐसी परिस्थितियों में, रिकॉर्ड करने में देरी गवाहों के बयान कम करने का आधार नहीं हो सकते हैं। इसका प्रमाणिक मूल्य या इसे पूरी तरह से अनदेखा करना। द हाई घटना एक ही क्षेत्र के निवासी थे और जानते थे हमलावरों और यह अपीलार्थियों का मामला नहीं था, कि देरी के परिणामस्वरूप गलत पहचान हो सकती थी अभियुक्त का। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार पुष्टि की जाती है। [रस 12,13] [758-जी-एच; 759-ए-सी; 760-डी]

3. उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की पुनः सराहना की गवाहों ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विस्तार से और सावधानीपूर्वक जांच की और एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला। के खिलाफ अपील में बरी किए जाने पर, अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया जाता है। उच्च न्यायालय को पूरे मामले की पुनः सराहना करने का अधिकार है। यह पता लगाने के लिए कि क्या निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं विचारण न्यायालय द्वारा विकृत या अनुचित हैं। [पारस 16, 17] [762 - ई-एफ, जी-एच; 763-ए]

संवत सिंह और अन्य। बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1961 एससी 715 : 1961 एस. सी. आर. 120 पर भरोसा किया।

4. गवाहों के साक्ष्य को दबाया नहीं जा सकता है। केवल कुछ मामूली विरोधाभासों के कारण, विशेष रूप से कारण है कि साक्ष्य और गवाहों की गवाही विश्वसनीय होती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि, गवाहों ने लगातार गवाही दी है अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपराध और उनके साक्ष्य के संबंध में उनके क्रूस के दौरान अडिग रहते हैं। जाँच। गवाहों के बयानों में केवल मामूली भिन्नता और विरोधाभास एक आधार नहीं हो सकता है चश्मदीद गवाह की गवाही को त्याग दें जो कोई नहीं है लेकिन एक मृतक की विधवा। इसके अलावा, [2013] 5 एस. सी. आर. 748 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट संबंध एक गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। [पैरा 19] [763-जी-एच; 764-ए-बी]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य। (2011) 4 एससीसी 324 : 2011 (4) एस. सी. आर. 1176-पर निर्भर था।

5. की ओर से बहुत जोर दिया गया है मृत शरीरों और लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी न होने पर अपीलकर्ता जब आरोप है कि हत्या के बाद जिन व्यक्तियों ने शवों को बोरे में डाल दिया। उपरोक्त याचिका किसी भी तरह से मामले में सुधार नहीं कर सकती है। अपीलार्थियों से। पीड़ित के

शव की खोज को कभी भी साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं माना गया है हत्या में कार्पस डिलिक्टि। वास्तव में, बहुत सारे हैं एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, सिख समुदाय पर इस तरह का हिंसक हमला स्थानों और अपराधियों ने शवों को हटाने की कोशिश की और सामान भी लूट लिया। एक हत्या के मामले में साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि शवों को उपलब्ध कराया गया हो, शव की पहचान और खोज अनिवार्य नहीं है। आई. पी. सी. की धारा 299 की प्रयोज्यता के लिए नहीं। [पारस 14,20, 21] [760 - ई-एफ; 765-सी-डी; 766-ई-एफ]

दिल्ली प्रशासन बनाम त्रिभुवन नाथ और अन्य। (1996) 8 एससीसी 250:1996 (1) पूरक। एस. सी. आर. 184-पर निर्भर। गोविंदराजू बनाम कर्नाटक राज्य (2009) 14 एससीसी 236; लोकेमान शाह और अन्र। बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2001) 5 एससीसी 235: 2001 (2) एस. सी. आर. 1095; रामानंद और अन्य। बनाम। एच. पी. राज्य (1981) 1 एस. सी. सी. 511: 1981 (2) एससीआर 444 और राम बहादुर उर्फ डेनी बनाम। राज्य 1996 Crl.L.J. 2364-संदर्भित को।

6. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अपराध का निष्कर्ष है मुख्य रूप से माइनर लाल बहादुर और ओआरएस के आधार पर चुनौती दी गई थी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 749 साक्ष्य में विसंगतियाँ। अब तक तत्काल मामला है संबंधित, वे छोटी विसंगतियाँ मामले की जड़ तक नहीं

जाएंगी और मामले के मूल संस्करण को हिला देंगी। गवाह जब वास्तव में महत्वपूर्ण संभावनाएँ हों कारक गवाहों द्वारा वर्णित संस्करण के पक्ष में प्रतिध्वनित होता है। [पैरा 22] [766-जी-एच]

भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य (1983)3 एससीसी 217:1983 (3) एससीआर 280 और लीला राम (मृत) दुली चंद बनाम हरियाणा राज्य और अन्न के माध्यम से। (1999) 9 एससीसी 525 1999 (3) पूरक। एस. सी. आर. 435-पर निर्भर।

7. पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर चश्मदीद गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के गवाह, अर्थात् पीडब्लू-1, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-7, यह पाया गया है कि कुछ मामूली लोगों को छोड़कर उनकी गवाही अडिग रही। विसंगतियाँ जिन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्यों के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सही सराहना की और इसे उलट दिया विचारण न्यायालय के निष्कर्ष। [पारस 23,24] [769-बी-डी]

मामला कानून संदर्भः

(2009) 14 एससीसी 236	संदर्भित	पैरा 9
2001 (2) एससीआर 1095	संदर्भित	पैरा 9
1981 (2) एससीआर 444	संदर्भित	पैरा 9

1996(1) पूरक। एस. सी. आर.184	पर निर्भर	पैरा 9
1996 Crl.L.J. 2364	संदर्भित	पैरा 9
1961 एससीआर 120	भरोसा किया	पैरा 18
2011(4) एससीआर 1176	भरोसा किया	पैरा 19
1996(1) पूरक। एस. सी. आर.184	संदर्भित	पैरा 20
1983 (3) एससीआर 280	भरोसा किया	पैरा 22
1999(3) पूरक। एस. सी. आर.435	पर निर्भर	पैरा 22

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1794/2008

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आपराधिक अपील संख्या 6/1992 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.08.2008 से उत्पन्न अपीलार्थियों के लिए प्रसून कुमार, क्षितिज कुमार, दीपक चंद्रपाल, वी. के. सिद्धार्थन।

राकेश खन्ना, एएसजी, जे. एस. अत्री, रश्मि मल्होत्रा, साधना संधू, हर्ष प्रभाकर, सीमा राव, प्रियंका प्रत्यर्थी के लिए भरीहोक, अनिल कटियार।

न्यायालय का निर्णय, **न्यायाधिपति एम. वाई. एक्बाल**, द्वारा पारित किया गया -

1. वर्तमान अपील दायर की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 379 के तहत जिसे उच्चतम न्यायालय की धारा 2 के साथ पढ़ा जाता है (दंड का विस्तार) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त, 2008 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार) अधिनियम, 1970, अतिरिक्त सत्रों द्वारा पारित 31 अक्टूबर, 1990 के बरी किए जाने के आदेश को पलटते हुए 1992 की आपराधिक अपील संख्या 6 न्यायाधीश, दिल्ली ने 1988 के सत्र मामले संख्या 12 में अपीलार्थियों को धारा 147/149/449 436/302/395 396 के तहत दोषी ठहराया। भारतीय दंड संहिता, 1860 और उनमें से प्रत्येक को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कारावास और जुर्माने से गुजरने की सजा आई. पी. सी. की धाराएँ।

2. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी सं. 4 राम कहा जाता है कि 23 मई, 2011 को लाल की मृत्यु हो गई थी। इसलिए, जहाँ तक उसका संबंध है, अपील समाप्त हो जाती है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि हाउस नं. 1 की निवासी हरजित कौर (पीडब्लू-1)आर. जेड.-1/295, गीतांजलि पार्क, पश्चिम सागरपुर, नई दिल्ली, उसके परिवार को नुकसान होने की आशंका दिवंगत प्रधानमंत्री की हत्या के बाद हुए दंगों के कारण मंत्री इंदिरा गांधी ने 31 अक्टूबर, 1984 को अपनी दोनों बेटियों और एक बेटे को अपने पिता गोविंद सिंह के घर लाल बहादुर एंड ओआरएस भेजा था। राज्य (एन. सी.

टी. दिल्ली) 751 [एम. वाई. एक्बाल, जे.] बी. ई.-7, हरि नगर, नई दिल्ली। अपनी टाइप की गई शिकायत में (उदा. पीडब्लू1/ए) ने 7 नवंबर, 1984 को दर्ज कराया, उन्होंने कहा कि एक भीड़ उसके पड़ोस ने उसके घर पर हमला किया था और लूटपाट की थी घरेलू सामान 1 नवंबर, 1984 को लगभग 9/9:30 बजे। साम्प्रदायिक हिंसा की धमकियों के डर से शिकायतकर्ता हरजित कौर और उनके परिवार ने डॉ. हरबीर शर्मा (पीडब्लू-5) के आवास पर शरण ली थी, जिनका घर शिकायतकर्ता के घर के सामने था और वे अपने पति के साथ वहीं रह रहे थे। 3 नवंबर, 1984 को अपीलकर्ता सुबह डॉ. हरबीर शर्मा के घर आए और उनके खिलाफ अपील करने का विरोध किया। शिकायतकर्ता के परिवार को आश्रय दिया और धमकी दी कि अगर शिकायतकर्ता और उसका परिवार जिसे आश्रय दिया गया था उन्हें नहीं सौंपा जाता था, वे घर जला देते थे। इसके बाद डॉ. हरबीर शर्मा सेना से मदद लेने के लिए निकले। लगभग 9 बजे अपीलार्थियों सहित 500 से अधिक लोगों की भीड़ आई और डॉ. के घर पर हमला कर दिया। हरबीर शर्मा जहाँ शिकायतकर्ता उसके साथ छिपी हुई थी पति और ससुर। अपीलकर्ताओं के पास एक था तेल और लोहे के सब्बल की बेंत और भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके पति और एफ ससुर ने लिया था भूतल पर एक कमरे में आश्रय और बंद स्वयं, जबकि डॉ. हरबीर शर्मा और उनका परिवार वह खुद ऊपर छत पर चली गई थी। उस समय भीड़ थी एकत्रित होते हुए, शिकायतकर्ता एक की छत पर मौजूद था डॉ. हरबीर शर्मा के पड़ोसी जिनका घर वहाँ था। एक ही

पंक्ति। शिकायतकर्ता की गवाही के अनुसार, भीड़ सशस्त्र थी सबल, बल्लम, साड़ी और लाठियों के साथ। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं ने घर के दरवाजे पर लोहे की सबलों से हमला किया लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ा जा सका। इसके बाद उन्होंने तोड़ दिया घर की खिड़की खोलकर अंदर घुसे और घर में आग लगा दी। शिकायतकर्ता के पति और ससुर को जिंदा जला दिया गया और उनके आधे जले हुए शरीर को बोरे में डाल दिया गया। द.शिकायतकर्ता का घर भी जला दिया गया। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि सुशील कुमार (पीडब्लू-4) (डॉ. हरबीर शर्मा के बहनोई), डॉ. हरबीर शर्मा (पीडब्लू-5), जगदीश (पीडब्लू-6) और मोहर पाल (पीडब्लू-7) ने भी घर और मृतक को आग लगाते हुए देखा। राजिंदर सिंह और सरदूल सिंह पर हमला किया जा रहा था, उन्हें जला दिया जा रहा था और उनके शवों को बोरे में डाल दिया जा रहा था। डॉ. शर्मा के घर में आग लगते देख सुशील कुमार डॉ. शर्मा को फोन करने के लिए दौड़े थे, जो डॉक्टर शर्मा को फोन करने गए थे। पुलिस। वे दोनों घर को जलता हुआ देखने के लिए वापस भागे अपीलार्थियों और सरदूर सिंह के साथ-साथ राजिंदर सिंह द्वारा मारे गए। उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक के शवों को बोरे में डालने के लिए डंडों का उपयोग करते देखा। हालांकि, कुछ वहाँ जमा हुए लोगों ने डॉ. शर्मा और उनके परिवार को बचाया। सदस्यों और उन्होंने 5 नवंबर, 1984 को रिपोर्ट दाखिल की। शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, दुर्घटना के बाद, एक लड़के की मदद से वह अपने पिता के घर हरि नगर गई और पुलिस स्टेशन जनकपुरी में भी और गोरखा रेजिमेंट की मदद मिलने के

बाद वह 3 तारीख को सागरपुर लौट आई। नवंबर, 1984 लेकिन वह अपने पति और ससुर के शव नहीं ले सकी और उसका पूरा घर जला दिया गया। घरेलू सामान के साथ डॉ. शर्मा का घर भी पूरी तरह से जल गया था। 7 नवंबर, 1984 को उन्होंने एक दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में शिकायत। एफ. आई. आर. 9 नवंबर, 1984 को दर्ज की गई थी। जाँच पूरी होने पर, अभियुक्तों-अपीलार्थियों के खिलाफ चालान दायर किया गया था और उन पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था आईपीसी की। अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों से पूछताछ की। प्रत्येक अभियुक्त ने इनकार किया दोषी ठहराने वाली परिस्थितियाँ उनके सामने रखी गईं और कहा कि वे गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि डॉ. हरबीर शर्मा की उनसे दुश्मनी थी। हालांकि, किसी भी आरोपी ने किसी का नेतृत्व नहीं किया बचाव में सबूत।

4. निचली अदालत की गवाही पर विचार करने पर गवाहों ने माना कि अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा है, अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सभी उचित से परे हैं संदेह किया और अभियुक्त अपीलार्थियों को बरी कर दिया।

5. निचली अदालत ने सबसे पहले कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी ठीक से समझाया नहीं गया क्योंकि शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) 3 नवंबर, 1984 को जनकपुरी पुलिस स्टेशन गया था और मृत लोगों को बरामद करने के लिए वहां से सैन्य मदद मांगी थी उनके पति और ससुर

के शव, लेकिन उन्होंने 3 नवंबर, 1984 को रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसी तरह, अदालत ने कहा कि डॉ. हरबीर शर्मा (पीडब्लू-5) की ओर से 5 नवंबर, 1984 को पुलिस में शिकायत करने में देरी हुई। 3 नवंबर, 1984 की घटना। निचली अदालत ने पी. डब्ल्यू.-4, पी. डब्ल्यू.-6 और पी. डब्ल्यू.-6 के बयान दर्ज करने में 27 दिनों की देरी भी देखी। पीडब्लू-7. दूसरा, निचली अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता ने दो अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात अपीलार्थी सं. 2 सुरेंडर और अपीलार्थी की उपस्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित बयान दिए गए पुष्टि के साथ-साथ आधे जले हुए मृत लोगों को रखने के संबंध में भी 3 नवंबर, 1984 को बोरे में शव क्योंकि उसने अपनी शिकायत (एक्स.पीडब्लू1/A) में अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 4 (राम लाल) और अपीलार्थी सं. 3 (विरेन्द्र सिंह) का नाम नहीं लिया था, हालाँकि अदालत में उनके द्वारा उनकी पहचान की गई थी। और यहाँ तक कि उसके अंदर भी दूसरी बार दर्ज किया गया बयान जिसमें उसने कहा था कि उसने अभियुक्त को नहीं देखा गया-अपीलार्थी सं. 2 सुरेंदर और अपीलार्थी सं. 3 1 नवंबर, 1984 को वीरेंदर ने अपने पहले कार्यकाल में 21 अप्रैल, 1986 को दर्ज किए गए बयान में उन्होंने कहा था कि 1नवंबर, 1984 अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 1 लाल बहादुर, अपीलार्थी नं. 3 विरेन्द्र आ अपीलार्थी नं. 4 राम लाल छलाह। उन लोगों के बीच जिन्होंने उसका घर लूटा था। ट्रायल कोर्ट आगे उल्लेख किया कि उसकी शिकायत में (उदा. पीडब्लू1/ए), शिकायतकर्ता उल्लेख किया था कि उसके पति के आधे जले हुए शव और ससुर को अभियुक्त (लाल बाबू, अदालत के समक्ष

बयान में उसने कहा कि उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया था देखें कि आरोपी मृतकों के जले हुए शवों को अंदर डाल रहा है बोरे और उसने केवल आरोपी व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना ' आधे जले हुए शवों को बोरे में डाल दें। तीसरा, मुकदमा अदालत ने आंखों के बयानों में कुछ विरोधाभासों को देखा गवाह, सुशील कुमार (पीडब्लू-4), डॉ. हरबीर शर्मा (पीडब्लू-5), जगदीश (पीडब्लू-6) और मोहर पाल (पीडब्लू-7)। ट्रायल कोर्ट इस बात पर ध्यान दिया कि शिकायत में कुछ तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। (पीडब्लू-5 द्वारा एक्स.पीडब्लू-5/1) और दो अभियुक्तों राम लाल और विरेंद्र के नाम भी उसमें उल्लेख नहीं पाए गए। ट्रायल कोर्ट में इंगित विरोधाभासों के आधार पर आगे देखा गया बयान कि पीडब्लू-5 वापस नहीं आया था और अपने घर के जलने के साथ-साथ मृत व्यक्तियों की पिटाई और हत्या को देखा था, जैसा कि उसने अपदस्थ किया था। चौथा, ट्रायल कोर्ट यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 और पीडब्लू अगर ऐसा होता तो पीडब्लू-5 ने निश्चित रूप से उनके नामों का उल्लेख किया होता। पूर्व में। पीडब्लू 5/1 और माना कि पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 की संभावना और पीडब्लू-7 की खरीद की जा रही है या पीडब्लू के लिए गवाही दी जा रही है 5 इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। निचली अदालत ने इस प्रकार निर्णय दियाः

> “इन सभी परिस्थितियों में 11 दिनों की देरी $ 4 पूर्व एफ. आई. आर. दर्ज करना। पीडब्लू1/ए, ठहरने में 2 दिनों

की देरी शिकायत एक्स पीडब्लू5/1, दो के नामों का उल्लेख नहीं एफ. आई. आर. के साथ-साथ मामले में भी आरोपी विरेंद्र और राम लाल रुचि के तत्व के साथ शिकायत पीडब्लू का हिस्सा, इस तथ्य के साथ कि पीडब्लू 4, पीडब्लू 6 और पीडब्लू 7 के बयान एक अन्यायपूर्ण बयान के बाद दर्ज किए गए हैं और 27 दिनों की लंबी देरी, अभियोजन पक्ष की कहानी में और मेरी कहानी में रैप और वूफ यानी बनावट पर संदेह करें। राय है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं है।

मेरी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूँ कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है संदेह की छाया। इस प्रकार संदेह का लाभ देते हुए मैं सभी को बरी कर देता हूँ। अभियुक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोप लगाया। वे जमानत पर हैं, उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं। मुचलके खारिज कर दिए जाते हैं। ..... "

6. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी। डिवीजन बेंच निचली अदालत के उपरोक्त निष्कर्षों को उलट दिया और दोषी ठहराया अभियुक्त-धारा

147/149/449/436/302/395/के तहत अपीलार्थी 396 , आई. पी. सी. और उनमें से प्रत्येक को अपराधों के लिए सजा सुनाई गई आईपीसी की उपरोक्त धाराओं के तहत किया गया।

7. यह इन परिस्थितियों में है कि वर्तमान अपील अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा धारा 379 के तहत दायर की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के साथ पढ़ा जाता है दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को पलटते हुए अदालत।

8. श्री प्रसून कुमार, अपीलार्थी के विद्वान वकील अभियुक्त व्यक्तियों ने पारित विवादित फैसले पर हमला किया उच्च न्यायालय को अवैध और कानून में विकृत होने के रूप में। सीखा है। चश्मदीद गवाहों के बयान की सराहना करते हुए कि चश्मदीद गवाहों का बयान संदेह से परे नहीं है और पूर्ण है विरोधाभासों, विसंगतियों और प्रतीक चिन्हों और आगे कथित चश्मदीद गवाहों द्वारा दी गई गवाही विश्वसनीय और विश्वसनीय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी डॉ. हरबीर शर्मा (पीडब्लू-5),सुशील कुमार के बयानों के संबंध में निचली अदालत का अवलोकन (पीडब्लू-4),जगदीश (पीडब्लू-6) और मोहर पाल (पीडब्लू-7) इंगित किया कि इसमें कुछ विरोधाभास हैं पीडब्लू-5 का बयान और उसकी शिकायत में एक्स पीडब्लू-5/1। सीखा है। वकील ने तब तर्क

दिया कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 (हरजीत कौर) के बयान में विरोधाभासों की सराहना नहीं की है। शिकायत के अनुसार पूर्व। पीडब्लू1/ए और पीडब्लू का विवरण 1, यह घटना दो तारीखों यानी पहली तारीख को हुई थी। नवंबर, 1984 और 3 नवंबर, 1984। 1 नवंबर को, 1984 , आरोपी लाल बाबू, सुरेंद्र और एक चरण जिसका पुलिस द्वारा चालान नहीं किया गया है, ने कुछ राशि एकत्र की है। अन्य लोग, उसके घर आए और घर को लूट लिया लेख। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वह सब कुछ जानती थी, चार आरोपी व्यक्ति क्योंकि वे उसके इलाके के निवासी थे और डेक में उनकी पहचान की, लेकिन उन्होंने एक्स पीडब्लू-1/A में आरोपी राम लाल और विरेंद्र का नाम नहीं लिया है। पीडब्लू-1 एकमात्र आँख है। 1 तारीख को हुई घटना के बारे में गवाह नवंबर, 1984 और अभियोजन पक्ष से संबंधित अन्य गवाह 3 नवंबर, 1984 की घटना क्योंकि उन्होंने गवाही नहीं दी है 1 नवंबर, 1984 की घटना के बारे में। इसके अलावा, पीडब्लू 1 अपनी शिकायत में राम लाल और विरेंद्र का नाम नहीं लिया है जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उसने यह भी बयान दिया है कि उसने अपने घर से भीड़ द्वारा लूटी गई वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने न तो लूटी गई वस्तुओं की कोई सूची रखी है, जैसा कि पीडब्लू-1 ने आरोप लगाया है और न ही किसी से कोई बरामदगी हुई है। लूटे गए के संबंध में अभियुक्त या किसी भी स्थान से लेख जाँच अधिकारी द्वारा प्रभावित किए गए हैं। इस प्रकार, पीडब्लू-1 की गवाही के संबंध में कोई पुष्टि नहीं है। लूट/डकैती की घटना, जो 1 तारीख

को हुई थी नवंबर, 1984। इसके अलावा, उच्च न्यायालय विफल रहा है इस बात की सराहना करें कि आई. पी. सी. की धारा 390 के तत्व नहीं बनाए गए हैं। वर्तमान मामले में बिल्कुल बाहर। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों की सराहना नहीं की क्योंकि एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था डकैती, सबसे पहले एक डकैती होनी चाहिए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने सराहना नहीं करके कानून में गलती की सुशील कुमार की गवाही में विसंगतियां/विरोधाभास (पीडब्लू-4), जगदीश (पीडब्लू-6) और मोहर पाल (पीडब्लू-7), जो थे बरी करने का आदेश पारित करते समय निचली अदालत द्वारा उचित रूप से सराहना की गई। पीडब्लू-4 पीडब्लू-5 का सह-भाई (साधु) है। उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उन्होंने एक कम्पाउंडर के रूप में काम किया था। पीडब्लू-6 के अनुसार, उन्होंने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को उपरोक्त दो घरों में आग लगाते, पीटते और मारते हुए देखा। मृतक और मृतक के शवों को भी डालना कई अन्य व्यक्तियों के साथ बोरे में जो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि उनका बयान दर्ज किया गया था 4-5 घटना के दिन जबकि वास्तव में बयान के अनुसार आई. ओ. (पीडब्लू-9) और अभिलेख के अनुसार उनका बयान दर्ज किया गया था। मृतकों में से, राजिंदर सिंह और सरदूल सिंह। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं किया निचली अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर महत्वपूर्ण/वैज्ञानिक साक्ष्य कि 3 नवंबर, 1984 को किसी भी व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। परिसर सं। आरजेड-3/295, गीतांजलि पार्क, सागरपुर, नई दिल्ली दिल्ली। अभियोजन

पक्ष के पास संग्रह करने के पर्याप्त अवसर थे राख, रक्त जैसी कथित घटना के स्थान से साक्ष्य दो लाल बहादुर और ओ. आर. एस. की कथित हत्या और जलाने को साबित करने के लिए दाग आदि जीवित लोग। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च अदालत ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि प्राथमिकी दर्ज करने में 07 दिनों की देरी हुई, क्योंकि कथित घटना हुई थी दो अलग-अलग तिथियों यानी 1 नवंबर, 1984 और 3 नवंबर को नवंबर, 1984। पीडब्लू-1 के अनुसार, वह 3 नवंबर को पुलिस/सैन्य सहायता को फोन करने गई थी। 1984 और वह पुलिस स्टेशन जनकपुरी में मौजूद थी, लेकिन यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उसके द्वारा 3 तारीख को प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी नवंबर, 1984 में ही। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार नहीं किया कि एक के रूप में स्पष्टीकरण देरी के औचित्य के लिए तर्क न केवल अनुचित है, बल्कि अनुचित भी है। अनुचित और काल्पनिक। उच्च द्वारा दिया गया कारण एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी के बारे में अदालत गलत और विकृत है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए। यह एक स्वीकृत है तथ्य यह है। पीडब्लू-1 हरजित कौर पुलिस को बुलाने गई और वह अधिकारियों के साथ एक सैन्य ट्रक में पुलिस स्टेशन से वापस आई। गोरखा रेजिमेंट की महिला के पास पुलिस को पूरी घटना बताने के लिए पर्याप्त समय था, इसलिए पीडब्लू-1 का यह इनकार कि उसने 3 नवंबर,1984 को पुलिस को पूरी घटना नहीं सुनाई थी, अविश्वसनीय है और इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता

है जो भी हो। आगे का तर्क यह है कि उच्च न्यायालय विफल रहा इस बात की सराहना करते हैं कि चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 का बयान 27 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के बाद दर्ज किया गया था जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। यह तथ्य सावधानीपूर्वक था, अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी करते समय विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया।

9. इसके विपरीत श्री राकेश खन्ना ने अतिरिक्त जानकारी ली। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और प्राप्त निष्कर्ष विधि में विकृत हैं और इसलिए, उच्च न्यायालय का अपीलीय शक्ति ने मुकदमे के निष्कर्षों को सही ढंग से उलट दिया है अदालत। शिक्षित ए. एस. जी. ने गवाही की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, अभियोजन पक्ष के गवाहों और प्रस्तुत किया कि नाबालिग को छोड़कर विसंगतियाँ अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में सक्षम रहा है। सवाल पर साक्ष्य की सराहना और गैर एच. पी., (1981) 1 एस. सी. सी. 511 सीखा हुआ ए. एस. जी. भी इस पर निर्भर करता है दिल्ली प्रशासन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय बनाम त्रिभुवन नाथ और अन्य, (1996) 8 एस. सी. सी. 250 जो मामला भी है 1984 के कुछ उदाहरणों से संबंधित जब सिख समुदायों पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन शव नहीं थे] ठीक हो गया।

10. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है दोनों तरफ से विद्वान वकील और गवाहों की गवाही का विश्लेषण किया। द्वारा किए गए विभिन्न निर्णय वकील पर भी हमारे द्वारा विचार किया गया है।

11. शुरुआत में, हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि तत्काल घटना, जैसा कि आरोप लगाया गया है, एकमात्र घटना नहीं है, लेकिन विशेष रूप से दिल्ली में जहां एक के कई निर्दोष व्यक्ति हैं समुदाय की हत्या कर दी गई थी और उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया था प्रधानमंत्री की हत्या के कारण लूटा गया, यह देश, जो 31 अक्टूबर, 1984 को हुआ था। प्रधानमंत्री की हत्या की चौंकाने वाली खबर सुनने के बाद मंत्री महोदय, विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों में भीड़ बनाने वाले हजारों लोगों ने सिख समुदायों पर अत्याचार किए और उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें आग लगा दी गई। इसलिए, सबूत साक्ष्य में मामूली विसंगतियों और विरोधाभासों में गए बिना सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए।

12. देरी के संबंध में पहले मुद्दे पर उच्च न्यायालय एफ. आई. आर. दर्ज करने में कहा गया कि वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ असाधारण हैं क्योंकि देश सांप्रदायिक दंगों में घिरा हुआ था। कर्फ्यू लगा दिया गया था, सिख परिवारों को अनियंत्रित और कट्टर पुरुषों की भीड़ द्वारा निशाना बनाया जा रहा था जो खत्म होने से डरते नहीं थे 30 तारीख को पुलिस द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करना नवंबर, 1984 में 27 दिनों की देरी के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा कि शहर उथल-

पुथल में था और लोगों के पास था प्रत्यक्ष अपराध स्वाभाविक रूप से आशंकित और भयभीत करने वाले होते हैं। अपराधियों के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आना, जब तक कि चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं; कि राज्य तंत्र पर बहुत अधिक काम किया गया था; और ऐसी परिस्थितियों में, गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी इसके साक्ष्य मूल्य को कम करने या इसे पूरी तरह से अनदेखा करने का आधार नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि घटना से पहले के गवाह उसी के निवासी थे क्षेत्र और हमलावरों को जानते थे और यह मामला नहीं था अपीलकर्ताओं का कहना है कि देरी का परिणाम गलत हो सकता है, अभियुक्त की पहचान।

13. विभिन्न की गवाही में विरोधाभासों के संबंध में गवाहों, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

> "19. ..... हरजित कौर ने उल्लेख किया था कि उनका घर था लाल बाबू की भीड़ द्वारा लूटी गई और सुरिंदर। उसके बाद अन्य लोगों के नामों का उल्लेख किया गया उत्तरदाताओं में सुधार नहीं दिखाई देता है इतना महत्व कि उसका पूरा चश्मदीद गवाह जो बताता है, अन्य गवाहों द्वारा पुष्टि को अनदेखा किया जा सकता है। सबसे अच्छा यहाँ एक संदेह केवल के संबंध में उत्पन्न हो सकता है विरेन्द्र और रामलाल की मिलीभगत (ऐसा प्रतीत होता है

कि निचली अदालत के फैसले में गलती से सुरिंदर के रूप में टाइप किया गया)क्योंकि बाद में उसने अन्य उत्तरदाताओं की पहचान की थी, विरेन्द्र आ रामलाल सेहो एहिमे भाग लेने छलाह। उसके घर को लूटना।

XXX XXX XXX

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पड़ोसियों और पीड़ित की विधवा पर निर्भर करता है जो दोषसिद्धि प्राप्त करने में रुचि रख सकता है, अभियुक्त व्यक्ति लेकिन कानून का कोई नियम यह निर्धारित नहीं करता है कि दोषसिद्धि इस तरह की गवाही पर आधारित नहीं हो सकती है गवाह। कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि गवाही उन गवाहों को ठोस और विश्वसनीय होना चाहिए।

यहाँ यह गवाही के सार को निकालने के लिए उपयुक्त है पीडब्ल्यूएस। .....

XXX XXX XXX

27. उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य को पढ़ने पर, हम पता लगाएँ कि गवाहों की गवाही विश्वसनीय है। यह हम इस तथ्य के कारण कहते हैं कि उनके साक्ष्य निरंतर रहे हैं

और वे भी अडिग रहे हैं। उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान। इस प्रकार, हम कोई नहीं पाते हैं इन गवाहों के साक्ष्य को खारिज करने का कारण समग्रता। वे किसी भी भौतिक तथ्य पर किसी भी तरह से भिन्न नहीं होते हैं और अगर कोई विसंगतियाँ हैं, तो वे तुच्छ हैं, महत्वहीन और इसका आधार नहीं बनाया जा सका दोषमुक्त "।

हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई दलीलों को खारिज करते हैं।

14. अपीलार्थियों के इस तर्क पर कि शव कभी बरामद और नहीं पाए गए थे और इस तरह कोई नहीं है इस तथ्य के संबंध में सबूत कि वे कभी मारे गए थे और वह भी अभियुक्त द्वारा,उच्च न्यायालय ने राम नंद का हवाला देते हुए & ओआरएस। बनाम। एच. पी. राज्य, (1981) 1 एस. सी. सी. 511 और राम बहादुर उर्फ डेनी बनाम राज्य, 1996 Crl.L.J. 2364 ने देखा कि यह ठीक है। स्थापित कानून जो हत्या के मामले में मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शवों को होना चाहिए मृत शरीर की पहचान और खोज के लिए उपलब्ध कराया गया है जो धारा 299 आईपीसी की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य नहीं है।

15. गवाहों या उनकी स्वतंत्रता के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि खरीद या उनकी रुचि कि निचली अदालत द्वारा बताए गए कारक केवल एक चिकित्सक रोगी या छात्र संघ का संबंध लेकिन नहीं दिखाता है कि सभी गवाहों ने कुछ गलत उद्देश्यों के साथ अभियुक्त के खिलाफ सांठगांठ की थी। शत्रुता के आरोप के संबंध में, नहीं साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था। इस मुद्दे में पाया गया कि "शत्रुता या शत्रुता का कोई सुझाव नहीं है हरजित कौर के साथ संबंध। डॉ. हरबीर शर्मा के लिए हरजित कौर के लिए गवाह जुटाने का कोई कारण नहीं होगा। डॉ. हरबीर शर्मा की रुचि केवल दावा करने में हो सकती थी। घर को जलाने के लिए मुआवजा, जो किसी भी मामले में उपलब्ध था क्योंकि घर को जलाना स्वीकार किया गया था स्थिति इसके अलावा, उनमें से प्रत्येक निवासी था एक ही क्षेत्र और वे प्राकृतिक गवाह थे और लगाए नहीं गए थे जो हैं। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए देखा गयाः

> " 40. ..... हमारा विचार है कि एक का भी प्रमाण सुरिंदर, विरेंद्र, राम लाल और लाल नाम के उत्तरदाताओं को फंसाने के लिए चश्मदीद गवाह अपने आप में पर्याप्त थे। 01.11.1984 और 03.11.1984 पर उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए बहादुर। यहाँ, हमारे पास चार चश्मदीद

गवाह हैं, जो अपनी आँखों से,मृत व्यक्तियों की वीभत्स हत्या को देखा है ।

41. हम इस बात से भी आश्वस्त नहीं हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हो रही है या पीडब्लू4, पीडब्लू6 के बयान दर्ज करने में देरी और पीडब्लू7 ने मुकदमे को दूषित कर दिया है। केवल परीक्षा में देरी कुछ दिनों के लिए गवाहों को सभी मामलों में नहीं बुलाया जा सकता है। जहाँ तक अभियोजन पक्ष के मामले का संबंध है, जब देरी की व्याख्या की जाती है तो यह घातक होगा। कई हो सकते हैं कारणों से। मान लीजिए, तत्काल मामला दंगों से संबंधित है, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण हुई थी, जिसके कारण यह पूरी तरह से टूट गई थी कानून और व्यवस्था तंत्र। अराजकता शहर के हर नुक्कड़ पर फैला हुआ था। उपरोक्त में परिस्थितियों में, हमें लगता है कि देरी हुई है संतोषजनक ढंग से समझाया। देरी की अवधि चाहे जो भी हो, अदालत गवाहों की गवाही पर कार्रवाई कर सकती है यदि यह विश्वसनीय पाई जाती है। इसके अलावा, गैर के आरोप स्वतंत्र गवाह और डॉ. शर्मा की दुश्मनी उत्तरदाता प्रत्यक्षदर्शी पर संदेह नहीं कर सकते हैं। हरजित कौर का लेखा।

XXX XX

43. यह हत्या, लूट और डकैती का कोई सामान्य मामला नहीं है। जल रहा है। यह एक ऐसा मामला है जहां एक विशेष समुदाय के सदस्यों को अलग कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई और उनकी संपत्तियों को जला दिया गया और लूट लिया गया। ऐसी अराजकता जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूरजा राम बनाम राजस्थान राज्य, 1997 सी. आर. एल. जे. 51 में कहा गया है, न्यायालय ने भी समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कठोरता से निपटने के योग्य है। उचित निवारक के लिए उचित अपेक्षा जघन्य अपराध के लिए सार्वजनिक घृणा के अनुरूप अभियुक्त द्वारा किया गया। वाक्य होना चाहिए भविष्य के लिए एक संदेश भेजने के लिए निवारक।

44. अपराध की सजा उसी जड़ से आती है। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। उनका पाप बीज है। भयानक आतंक पैदा हुआ उनके द्वारा किया जाना समाज के लिए चिंता का विषय है। अदालतें हैं कानून द्वारा प्रभावी दंड लगाने के लिए सशक्त अभियुक्तों के साथ-साथ उन लोगों पर भी जो जघन्य अपराध करने में उनके भागीदार हैं।"

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने फिर से सराहना की गवाहों के साक्ष्य का विस्तार से और सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया सही परिप्रेक्ष्य में मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला।

17. विद्वान वकील श्री कुमार का तर्क अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होना यह है कि चूंकि निचली अदालत ने साक्ष्य की विस्तार से सराहना करने के बाद अपीलार्थियों को बरी कर दिया, इसलिए उच्च न्यायालय को आम तौर पर एक अलग दृष्टिकोण नहीं लेना चाहिए था। हम. विद्वानों द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं वकील। यह अच्छी तरह से तय प्रस्ताव है कि इसके खिलाफ अपील में बरी किए जाने पर, अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्ति होती है जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया जाता है। द हाई न्यायालय लाल बहादुर और ओ. आर. एस. के आदेश में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने का हकदार है। यह पता लगाने के लिए कि क्या निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या अनुचित हैं।

18. संवत सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से कानून का अच्छी तरह से निपटारा किया

गया है। बनाम। राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715 (पैरा 9), जिसमें यह न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> " पूर्वगामी चर्चा से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैंः(1) अपीलीय न्यायालय के पास साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्ति होती है। जिस पर दोषमुक्त करने का आदेश स्थापित किया गया है; (2) 398 : (ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2), ऐसे मामलों के निपटारे में अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण के लिए एक सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक अपील; और (3) में उपयोग किए गए विभिन्न वाक्यांश इस न्यायालय के निर्णय, जैसे, (i) "सारवान और बाध्यकारी कारण ", (ii)" अच्छे और पर्याप्त रूप से ठोस कारण ", और (iii)" मजबूत कारण ", का उद्देश्य नहीं है - पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने के लिए बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की निस्संदेह शक्ति को कम करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए; लेकिन ऐसा करते समय उसे न केवल रिकॉर्ड पर प्रत्येक मामले पर विचार करना चाहिए जिसका इस पर प्रभाव पड़ता है तथ्य के प्रश्न और न्यायालय द्वारा दिए गए कारण उसके बरी होने के आदेश के समर्थन में नीचे उन तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना चाहिए, लेकिन उन्हें

भी व्यक्त करना चाहिए अपने निर्णय में कारण, जो इसे यह मानने के लिए प्रेरित करते हैं कि बरी होना उचित नहीं था "।

19. जहाँ तक अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास और विसंगतियाँ हैं, जैसा कि अपीलार्थियों के वकील चिंतित हैं, हम चले गए हैं पूरे साक्ष्य के माध्यम से और पाया कि गवाहों के साक्ष्य को केवल कुछ कारणों से दरकिनार नहीं किया जा सकता है छोटे विरोधाभास, विशेष रूप से इस कारण से कि गवाहों के साक्ष्य और गवाही विश्वसनीय ugh हैं। केवल यह कि गवाहों ने लगातार इस संबंध में गवाही दी है अपीलार्थियों द्वारा किए गए अपराध और उनके साक्ष्य अपनी क्रॉस-परीक्षा के दौरान अडिग रहें। के बयानों में केवल मामूली भिन्नता और विरोधाभास चश्मदीद गवाह की गवाही को खारिज करने के लिए गवाह एक आधार नहीं हो सकते हैं, जो मृतक की विधवा के अलावा और कोई नहीं है। इसके अलावा, संबंध एक गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य के मामले में। (2011) 4 एस. सी. सी. 324, इस न्यायालय ने कहाः

" 30. सभी आपराधिक मामलों में, सामान्य विसंगतियां बाध्य हैं। सामान्य कारण से गवाहों के बयानों में होने के

लिए अवलोकन की त्रुटियाँ, अर्थात् स्मृति की त्रुटियाँ समय के अंतराल या सदमे जैसे मानसिक स्वभाव के कारण और घटना के समय भय। कहाँ चूक है एक विरोधाभास के रूप में, एक गंभीर संदेह पैदा करना गवाह और अन्य गवाहों की सच्चाई भी अदालत में गवाही देते समय सामग्री में सुधार करना, इस तरह के साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता है। हालांकि, मामूली विरोधाभास, विसंगतियाँ, अलंकरण या अभियोजन मामले के मूल को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिस पर साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। अदालत को विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनानी होगी गवाही दें और एक निष्कर्ष दर्ज करें कि क्या उसका बयान आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है।

> "9. अतिशयोक्तियाँ स्वयं प्रस्तुत नहीं करती हैं सबूत भंगुर। लेकिन यह अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए कारकों में से एक हो सकता है, जब पूरे साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखने के लिए एक क्रूसिबल में रखा जाता है। (एडः जैसा कि देखा गया है। बिभूति नाथ गोस्वामी

बनाम। शिव कुमार सिंह (2004) 9 एससीसी 186 पी। 192.

इसलिए, के बयानों में केवल मामूली भिन्नताएँ एक गवाह को सुधार के रूप में नहीं कहा जा सकता है यही लाल बहादुर और ओ. आर. एस. द्वारा दिए गए बयान का विस्तार हो सकता है। पहले गवाह। चूक जो राशि है भौतिक विवरणों में विरोधाभास अर्थात इसकी जड़ तक जाना मामला/मामले के मुकदमे या मूल को भौतिक रूप से प्रभावित करता है, अभियोजन पक्ष का मामला, गवाह की गवाही दें बदनाम किया जा सकता है। [राज्य बनाम। सरवनन, (2008) 17 एस. सी. सी. 587, अरुमुगम बनाम राज्य (2008) 15 एससीसी 590,महेंद्र प्रताप सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 11 एससीसी 334 , और सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉ.) बनाम। राज्य महाराष्ट्र से। (2010) 13 एस. सी. सी. 657]

20. विद्वान वकील ने शवों और लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी न होने पर बहुत जोर दिया है जब आरोप यह है कि व्यक्तियों को मारने के बाद उन्होंने बोरे में शव। उपरोक्त याचिका किसी भी तरह से अपीलार्थियों के मामले में सुधार नहीं कर सकती है। इस मामले में यह अदालत दिल्ली प्रशासन बनाम त्रिभुवन नाथ और अन्य, (1996)8 एस. सी. सी. 250 ने

उसी मुद्दे पर विचार किया है जिसे एस. सी. सी. 250 ने उठाया था। यहाँ अपीलार्थी। उस मामले में, अभियुक्तों पर हत्या करने और शव को नालियों में फेंकने के लिए मुकदमा चलाया गया था 1984 में प्रधानमंत्री की हत्या के कारण घर जला दिए गए थे। साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने के बाद, यह न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> " 5. यदि उपरोक्त पीडब्लू के साक्ष्य को एक के रूप में पढ़ा जाता है पूरा, जो होना चाहिए, हमने जो पाया वह 1-11 पर है 1984, सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे, लगभग 200 लोगों की भीड़। ब्लॉक नं. पी-1, सुल्तान पुरी, जिसके पास तब 30 से 35 जुग्गियाँ। मृतक हिम्मत सिंह और वजीर सिंह उन झुग्गियों में रहते थे। भीड़ जो आई कहा जाता है कि सुबह करीब 11 बजे वे लोहे से लैस थे। छड़ें और डंडे; लेकिन तब इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। बल्कि, इस भीड़ द्वारा यह सलाह दी जा रही थी कि व्यक्तियों यदि वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो झुग्गियों में रहने से उनके बाल कटवा लिए जाने चाहिए। कैदियों ने इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक महसूस किया सलाह दी और वे अपने बाल काटने की प्रक्रिया में थे। लेकिन फिर एक और भीड़ आई, जो पीडब्लू 11, के अनुसार थी। इस संख्या में 200-250 व्यक्ति शामिल हैं पीडब्लू 2 द्वारा 1000-1200 के रूप में

दिया गया है। पीडब्लू 4 के अनुसार भीड़ में 100 लोग शामिल थे। पीडब्लू 8 ने नंबर नहीं दिया। हम वास्तव में संख्या के बारे में चिंतित नहीं हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि भीड़ बहुत बड़ी थी। इस भीड़ ने तबाही मचाई और इस भीड़ के सदस्य भी पास के नाले में। पीडब्लू 2 ने भी कहा था कि भीड़ ने मारे गए लोगों को बगल के नाले में फेंक दिया। जैसा कि हजारों लोगों से इस तरह निपटा गया है, यह होगा कार्पस डिलिक्टि के उत्पादन की उम्मीद करने के लिए बहुत अधिक हो। हम इस स्तर पर ही इस पहलू का उल्लेख कर चुके हैं। क्योंकि जिन कारणों से उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को बरी किया, उनमें से एक कार्पस डिलिक्टि का गैर-प्रस्तुत होना है। हमें डर है कि उच्च न्यायालय ने स्थिति को गलत तरीके से पढ़ा। हुए आघात का गलत आकलन किया "।

21. यह अच्छी तरह से तय है कि पीड़ित के शव की खोज को कभी भी साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं माना गया है हत्या में कॉर्पस डिलिक्टि। वास्तव में, बहुत सारे मामले हैं ऐसी प्रकृति की जैसे कि वर्तमान की खोज मृत शरीर असंभव है,विशेष रूप से जब इस तरह की हिंसक भीड़ में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या कर दी गई हो विभिन्न स्थानों

पर सिख समुदाय पर हमला और अपराधी शवों को हटाने की कोशिश की और सामान भी लूट लिया।

22. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष को मुख्य रूप से विद्वान वकील द्वारा चुनौती दी गई है। साक्ष्य में मामूली विसंगतियों के आधार पर। जहां तक तत्काल मामले का संबंध है, वे मामूली विसंगतियां मामले की जड़ तक नहीं जाएंगी और मामले के मूल संस्करण को हिला देंगी। गवाह जब वास्तव में महत्वपूर्ण संभावना कारक होते हैं गवाहों द्वारा बताए गए संस्करण के पक्ष में प्रतिध्वनि। यह भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 217 ने अभिनिर्धारित किया कि निम्नलिखित पर मामूली विसंगतियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिएः

> "(1) मोटे तौर पर एक गवाह से उम्मीद नहीं की जा सकती है फोटोग्राफिक मेमोरी रखें और विवरणों को याद रखें एक घटना से। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो टेप को फिर से चलाया जाता है मानसिक स्क्रीन।
>
> (2) आम तौर पर ऐसा होता है कि एक गवाह घटनाओं से प्रभावित। गवाह नहीं हो सकता था उस घटना का अनुमान लगाया जिसमें अक्सर एक तत्व होता है आश्चर्य की बात।

इसलिए मानसिक क्षमताएँ नहीं हो सकतीं विवरण को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होने की उम्मीद है।

(3) अवलोकन की शक्तियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। जिसे एक देख सकता है, दूसरा नहीं भी देख सकता है। एक वस्तु या आंदोलन किसी व्यक्ति की छवि पर उभरा हो सकता है। दिमाग, जबकि यह दूसरे की ओर से किसी का ध्यान नहीं जा सकता है।

(4) बड़े पैमाने पर लोग सटीक रूप से याद नहीं कर सकते हैं बातचीत करें और उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को फिर से लिखें या उनके द्वारा सुना गया। वे केवल मुख्य उद्देश्य को याद कर सकते हैं बातचीत। गवाह होने की उम्मीद करना अवास्तविक है एक मानव टेप-रिकॉर्डर।

(5) किसी घटना के सटीक समय या समय के संबंध में एक घटना की अवधि, आमतौर पर, लोग अपनी अनुमान द्वारा अनुमान-इस समय के उत्साह पर काम करें पूछताछ का समय। और लोगों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसे मामलों में बहुत सटीक या विश्वसनीय अनुमान लगाएं। पुनः, यह व्यक्तियों की समय-बोध पर निर्भर करता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होती है।

(6) आम तौर पर एक गवाह से वापस बुलाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सटीक रूप से घटनाओं का क्रम जो घटित होता है त्वरित उत्तराधिकार या कम समय अवधि में। एक गवाह है भ्रमित होने के लिए, या बाद में पूछताछ करने पर भ्रमित होने के लिए उत्तरदायी पर।

(7) एक गवाह, हालांकि पूरी तरह से सच्चा है, होने के लिए उत्तरदायी है अदालत के माहौल और भेदी क्रॉस से परेशान काउंसल द्वारा की गई जाँच और घबराहट के मिश्रण से तथ्यों को सामने लाना, घटनाओं के क्रम के बारे में भ्रमित होना, या पल भरते ही कल्पना से विवरण भरें। कभी-कभी गवाह का अवचेतन मन ऐसा होता है मूर्ख दिखने या होने के डर के कारण काम करता है अविश्वासी हालांकि गवाह एक सच्चा और उसके द्वारा देखी गई घटना का ईमानदार विवरण शायद यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है। पल के उत्साह पर सक्रिय "।

लीला राम (मृत) के मामले में दुली चंद बनाम हरियाणा और अन्य (1999) 9 एस. सी. सी. 525, यह न्यायालय ने कहा:

" 11. न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग मामलों में अलग-अलग प्रतिक्रिया

देते हैं स्थितियाँः जबकि कुछ अवाक हो जाते हैं, कुछ शुरू कर देते हैं रोते हुए जबकि कुछ अन्य लोग घटनास्थल से भाग जाते हैं और फिर भी कुछ ऐसे हैं जो साहस के साथ आगे आ सकते हैं,विश्वास और विश्वास कि गलत को ठीक किया जाना चाहिए। वास्तव में यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है और व्यक्तियों। कोई सेट पैटर्न या वर्दी नहीं हो सकती है। उसकी प्रतिक्रिया एक निर्धारित पैटर्न के भीतर नहीं आने के आधार पर यह अनुत्पादक और एक पांडित्यपूर्ण अभ्यास है।

12. वास्तव में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शायद ही कोई एक गवाह के सामने आता है जिसके साक्ष्य में शामिल नहीं है कुछ अतिशयोक्ति या अलंकरण-कभी-कभी वहाँ यहाँ तक कि सजावट करने का जानबूझकर किया गया प्रयास भी हो सकता है। अतिशयोक्तिपूर्ण लेखा। कोर्ट भूसी को निकाल सकता है अनाज और गवाही से सच्चाई का पता लगाएं गवाह। साक्ष्य का पूरी तरह से खंडन अनावश्यक है। साक्ष्य पर दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए विश्वसनीयता। यदि यह तत्व संतुष्ट है, तो इसे स्वीकार करने के लिए अदालत के मन में विश्वास पैदा करें।"

23. हमने पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया है प्रत्यक्षदर्शी सहित अभियोजन पक्ष के गवाह, अर्थात्, पीडब्लू-1, अमरजीत कौर, पीडब्लू-4, सुशील कुमार, पीडब्लू-5, डॉ. हरबीर शर्मा, पीडब्लू-6, जगदीश कुमार, पीडब्लू-7, मोहर पाल। कि कुछ मामूली विसंगतियों को छोड़कर उनकी गवाही अडिग रही है जिन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

24. तथ्यों के उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए और अभिलेख पर साक्ष्य, हम अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से साक्ष्य की सराहना की और पलट दिया, विचारण न्यायालय के निष्कर्ष।

25. उपरोक्त कारणों से, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं, यह अपील तदनुसार खारिज की जाती है। याचिका खारिज कर दी गई।

बी. बी

अपील ख़ारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****